कीमत तय करने में एहतियात बरतें तेल उत्पादक देश : प्रधानमंत्री

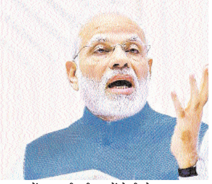

नई दिल्ली, 12 फरवरी (ए)। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर तेल उत्पादक देशों को चेताया है। मोदी ने कहा है कि तेल का उपभोग करने वाले देशों के लिए ही नहीं, बल्कि उसका उत्पादन करने वाले देशों के हितों के लिए भी यह जरूरी है कि तेल की कीमतें तय करने में सावधानी बरती जाए। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पेट्रोटेक-2019 का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि तेल की कीमतों के तय करने में सावधानी बरतना इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया में सभी को साफ, स्वच्छ और उचित कीमत पर ऊर्जा मिल सके।

पिछले वर्ष जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत में तेजी से इजाफा हो रहा था, तब नई दिल्ली में एनर्जी फोरम की बैठक में मोदी ने यही मुद्दा उठाया था। उस वक्त उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि तेल उपभोक्ता देश ऊर्जा के दूसरे स्रोतों की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। उसके बाद क्रूड की कीमतों में कमी आ गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके लिए भारत जैसे बड़े तेल उपभोक्ता देश के प्रधानमंत्री की तरफ से व्यक्त की गई चिंता भी एक वजह रही। वैसे, सोमवार को मोदी का लहजा चेतावनी वाला नहीं बल्कि सुझाव वाला था। इस बैठक में देश-विदेश के तेल व गैस विशेषज्ञों के बीच उन्होंने यह समझाना चाहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का दौर शुरू होने के बावजूद भारत जैसे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की अहमियत बनी रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता को और बढ़ाने का फैसला नहीं करता। भारत रिफाइनिंग क्षमता के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और वर्ष 2030 तक अपनी क्षमता में अतिरिक्त 20 करोड़ टन सालाना की वृद्धि की जाएगी। भारत की घरेलू रिफाइनिंग क्षमता अभी 23 करोड़ टन सालाना है। मोदी ने निवेशकों से कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में एक आकर्षक स्थल बना रहेगा क्योंकि यहां ऊर्जा की मांग वर्ष 2040 तक दोगुनी हो जाने के आसार है। यही नहीं, एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि ऊर्जा के उपभोग के तरीके और उत्पादन में बदलाव आ रहा है। अमेरिका अब सबसे बड़ा तेल व गैस उत्पादक देश बन गया है। ऊर्जा के दूसरे स्रोतों का विस्तार हो रहा है। प्राकृतिक गैस सबसे बड़ा स्रोत बनने की तरफ अग्रसर है। भारत भी तेजी से गैस की खपत को बढ़ाने में जुटा है। इसमें निजी निवेश को बढ़ाने के लिए भारत सरकार लगातार अपनी नीतियों में सुधार कर रही है।

महंगे क्रूड और कमजोर रुपये से स्पाइसजेट को 77% प्रॉफिट कम

नई दिल्ली, 12 फरवरी (ए)। सस्ती विमानन सेवा देने वाली कंपनी स्पाइसजेट का मुनाफा दिसंबर तिमाही में 77.1 फीसद कम हो गया। कंपनी ने इसके पीछे क्रूड ऑयल के दाम में तेजी और विदेशी मुद्रा के नुकसान को जिम्मेदार ठहराया है। एयरलाइन का शुद्ध लाभ दिसंबर में समाप्त तिमाही में 550.7 मिलियन (.7.74 मिलियन) रहा, जो एक साल पहले 2.40 बिलियन था। इस दौरान यात्रियों की संख्या और किराया आठ फीसद बढ़ा। एयरलाइन नियामक के अनुसार, दिसंबर तिमाही में स्पाइसजेट की तीसरी सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी थी, जिनमें पिछले तीन महीनों से कोई बदलाव नहीं हुआ था।आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में स्पाइसजेट का शेयर +2.42% फीसद की उछाल के साथ 78.40 पर बंद हुआ। एयरलाइन ने एक साल पहले की अवधि में 240 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। इस तिमाही में स्पाइस जेट की कुल आय 2,530.8 करोड़ रुपये रही, जो कि इसी अवधि की समान तिमाही में 2,096.1 करोड़ रुपये थी। स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने कहा कि एयरलाइन हमारी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है क्योंकि यह पहले ही नई उड़ानें पेश करती है, इसके अलावा सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का नेतृत्व करती है, साथ ही नए विमानों को शामिल करती है और हमारी लागतों को नियंत्रण में रखते हुए नए विकास के रास्ते तलाशती है। एयरलाइन के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में इसका औसत किराया 25 फीसद तक बढ़ाया गया जबकि रिपोर्टिंग तिमाही में इसका पैसेंजर लोड फैक्टर 91.6 फीसद रहा।

पीएफ पर FY19 के लिए 8.55 फीसद की ब्याज दर बरकरार रख सकता है EPFO

नई दिल्ली, 12 फरवरी (ए)। रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) पर ब्याज दर को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.55 फीसद पर बरकरार रख सकता है। फिलहाल ईपीएफओ से छह करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। यह जानकारी एक सूत्र के हवाले से सामने आई है। सूत्र ने बताया, ईपीएफओ के न्यासियों की 21 फरवरी को होने वाली बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर के प्रस्ताव को सामने रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्याज दर चालू वित्त वर्ष के लिये 2017-18 की तरह 8.55 प्रतिशत पर बरकरार रखा जाएगा। ईपीएफओ के आय अनुमान को बैठक में रखा जाएगा। हालांकि सूत्र ने इस अटकल को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर 8.55 फीसद से अधिक भी हो सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाला न्यासी बोर्ड ईपीएफओ का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है जो वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को अंतिम रूप देता है। एक बार न्यासी बोर्ड (सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) की अनुमति मिलने के बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से सहमति की जरूरत होगी। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ब्याज दर को अंशधारक के खाते में डाला जाएगा। गौरतलब है कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2017-18 में अपने सब्सक्राइबर्स को 8.55 फीसद ब्याज दिया।

NCLT अहमदाबाद के निर्णय लेने की तारीख को NCLAT ने 19 फरवरी तक बढ़ाया

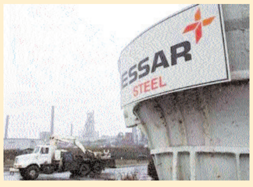

नई दिल्ली, 12 फरवरी (ए)। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने एनसीएलटी की अहमदाबाद शाखा को एस्सार स्टील मामले में निर्णय लेने के लिए एक और हफ्ते की मोहलत दे दी है। अब इसके पास 19 फरवरी तक का वक्त है। एनसीएलटी अहमदाबाद को कर्ज में डूबी एस्सार स्टील की शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संदर्भ में आर्सेलरमित्तल की ओर से लगाई गई 42,000 करोड़ रुपये की संकल्प योजना पर निर्णय करना है। न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने एनसीएलटी को आदेश दिया है कि वह इस मामले पर 19 फरवरी तक अपना निर्णय करे। सुनवाई के दौरान, एनसीएलएटी को सूचना दी गई थी कि अहमदाबाद पीठ ने परिचालन के लिए एस्सार स्टील को कर्ज देने वालों की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई है और मंगलवार को वह एस्सार के निलंबित निदेशकों का पक्ष सुनेगी। इससे पहले 4 फरवरी को, एनसीएलएटी ने एनसीएलटी अहमदाबाद से कहा था कि वो 11 फरवरी तक अपना फैसला सुनाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आर्सेलरमित्तल ने कर्ज में डूबी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए 42,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई है।

IPO के जरिए बाजार से पैसा जुटाएगी रिलायंस इंश्योरेंस

नई दिल्ली, 12 फरवरी (ए)। अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने नए सिरे से आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक निगम) के लिए आवेदन किया है। कंपनी को इससे पहले भी सेबी की तरफ से आईपीओ लाए जाने की मंजूरी मिली थी, जिसकी मियाद नवंबर महीने में खत्म हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के आईपीओ का आकार 200 करोड़ रुपये का होगा और साथ ही रिलायंस कैपिटल 79,489,821 शेयरों को ऑफर ऑफ सेल के तहत बेचेगी। कंपनी ने इस बार अपने आईपीओ को मैनेज करने वाली बैंकर्स के समूह से एडेलविज को हटा दिया है।

एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी बिक्री से 5,316 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है सरकार

नई दिल्ली, 12 फरवरी (ए)। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया मंगलवार से शुरू करेगी। सरकार बैंक में 'स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया' के माध्यम से रखी गई अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। यह जानकारी फाइलिंग के मुताबिक सामने आई है। सरकार की कोशिश 5,316 करोड़ रुपये जुटाने की है।

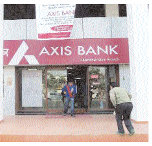

सरकार बैंक में तीन फीसद हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश दो दिनों के लिए करेगी जिसकी शुरुआत 12 जनवरी से होगी। यह सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में 80,000 करोड़ रुपये जुटाए जाने हैं। एक्सिस बैंक ने बताया, एसयूयूटीआई ने 12 फरवरी को एक्सिस बैंक के 5,07,59,949 इक्विटी शेयरों के बिक्री की पेशकश की है। शेयरों की इस बिक्री के लिए आधार मूल्य 689.52 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। यह बीएसई पर सोमवार को एक्सिस बैंक के प्रति शेयर 710.35 रुपये के बंद भाव से कम है। एक्सिस बैंक की प्रमोटर इकाई एसयूयूटीआई द्वारा रखे गए शेयरों को बिक्री के लिए रखा जाएगा। यह सेल मंगलवार को नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खोली जाएगी और बुधवार को खुदरा निवेशक (रिटेल इन्वेस्टर्स) इसके लिए बोली लगा सकते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक करेंगे एनपीए खातों की बिक्री

नई दिल्ली, 12 फरवरी (ए)।सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) ने करीब 5,740 करोड़ रुपये के लोन की रिकवरी के लिए विभिन्न सकंटग्रस्त (एनपीए) खातों को बिक्री के लिए रखा है। एसबीआई ने इसके लिए 4,975 करोड़ रुपये की राशि रिकवर करने के लिए संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) और वित्तीय संस्थानों से बोलियां मंगवाई हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बैंक की ओर से बिक्री के लिए रखे गए खातों में बड़ी संख्या में छोटे एवं मंझोले उद्यमों (एसएमई) के खाते शामिल हैं और उन पर बैंक का कुल 4,667 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं दूसरी तरफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) 13 एनपीए खातों की बिक्री करेगा, जिन पर कुल 764.44 करोड़ रुपये का बकाया है।

ट्विटर के सीईओ को संसदीय समिति फिर से भेजेगी समन, 25 फरवरी को पेशी के लिए बुलाने की तैयारी

नई दिल्ली, 12 फरवरी (ए)। संसदीय समिति, ट्विटर के सीईओ को फिर से समन जारी करने जा रही है। संसदीय समिति ने ट्विटर के सीईओ (चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर) समेत अन्य अधिकारियों को पिछली बैठक में बुलाया था, लेकिन उन्होंने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर गठित संसदीय समिति ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को 25 फरवरी को पेश होने के बुलाएगी।

समिति के चेयरमैन और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने ट्विटर के सीईओ को बुलाया था लेकिन वह पेश नहीं हुए और जूनियर अधिकारियों को भेज दिया। ठाकुर ने कहा कि संसदीय समिति ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और अगर डोर्सी दुबारा पेश नहीं होते हैं, तो इसे संसदीय विशेषाधिकारों का हनन समझा जाएगा। ट्विटर के अधिकारियों और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिकारियों को सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े उपायों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। ट्विटर की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है।

समिति ने एक फरवरी को ट्विटर को पत्र भेजकर समन किया था। पहले सात फरवरी को बैठक तय थी, लेकिन अब उसे 11 फरवरी को रखा गया ताकि ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी समेत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को आने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके बाद ट्विटर ने सुनवाई के लिए कम समय मिलने को कारण बताते हुए इन्कार किया था।

गौरतलब है कि यूथ फॉर सोशल मीडिया डेमोक्रेसी (वाईएसएमडी) ने ट्विटर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली स्थित इसके ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था।

31 जनवरी को अनुराग ठाकुर को सौंपे गए दस्तावेज में वाईएसएमडी ने कहा था, वामपंथी विचारधारा वाले उन खातों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो लगातार आक्रामक, गाली गलौच से भरपूर और धमकी वाले पोस्ट करते हैं। जबकि यह ट्विटर के नियमों के खिलाफ होता है। ट्विटर ने हालांकि, इन आरोपों का खंडन किया था।

2008 के बाद फिर से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आहट, अर्थशास्त्री ने चेताया

नई दिल्ली, 12 फरवरी (ए)।अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके मशहूर अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी के चपेट में आने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था वैसे समय में मंदी की तरफ से बढ़ती नजर आ रही है, जब देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के पास इससे निपटने की पर्याप्त ताकत नहीं है।

न्यूज वायर ब्लूमबर्ग के मुताबिक क्रुगमैन ने कहा, ऐसा लग रहा है कि छोटी समस्याएं जमा हो रही हैं और यह बता रहा है कि हमारे पास नीतिगत मोर्चे पर कोई अच्छी पहल नहीं बची है। गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में इजाफा नहीं किया था। क्रूगमैन ने कहा, लगातार ब्याज दरों को बढ़ाना बेहद बुरा विचार है। मंदी की आशंका जता चुके क्रूगमैन ही इकलौते अर्थशास्त्री नहीं है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने दिसंबर में एक सर्वे पेश किया था, जिसमें बताया गया था कि दो सालों के भीतर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है। क्रुगमैन ने कहा, मैं इतना निश्चित तो नहीं हूं। लेकिन यह जल्दी होगा। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि इस बार की मंदी, 2008 की तरह नहीं होगी। क्रुगमैन ट्रंप की आर्थिक नीतियों के प्रखर आलोचक रहे हैं।

2008 की मंदी से अभी तक उबर रही है वैश्विक अर्थव्यवस्था। गौरतलब है कि 2008 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के असर से उबरने में दुनिया को एक दशक से भी अधिक का समय लगा। अमेरिका के 'सब-प्राइम कर्ज संकट' की वजह से दुनिया रातों रात मंदी की चपेट में आ गई थी।

कर्ज नहीं चुका पाने वालों को अंधाधुंध कर्ज दिए जाने की वजह से जो संकट पैदा हुआ, उसमें अमेरिका के कई बैंक बर्बाद हो गए। 2018 के सितंबर में लीमन ब्रदर्स के दिवालिया होने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई।

भारत में रिफाइनरी और पेट्रोरसायन क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहता है यूएई

नई दिल्ली, 12 फरवरी (ए)। दुनिया का तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता और तेल संपन्न देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने सोमवार को कहा कि वह भारत में रिफाइनरी और पेट्रोरसायन क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहता है। तेल की लगातार बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए यूएई ने भारत के तेल भंडारों में अधिक तेल रखने की भी इच्छा जाहिर की।

यूएई की अबु धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) और इसकी भागीदार सऊदी आराम्को ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में प्रस्तावित 44 अरब डालर की रिफाइनरी एवं पेट्रोरसायन परियोजना में 50 फीसद हिस्सेदारी ली है। एडीएनओसी ने कर्नाटक के मंगलूर और पादुर में बने रणनीतिक भूमिगत तेल भंडारगृहों में भी अपना तेल रखने की पहल की है। यूएई के राज्य मंत्री और एडीएनओसी के सीईओ सुल्तान अहमद अल-जबर ने भारत में निवेश बढ़ाने की इच्छा जताते हुए कहा, हम विशेषतौर से भारत में रिफाइनिंग और पेट्रोरसायन क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूएई केवल भारत को कच्चा तेल बेचने वाला देश बनकर नहीं रहना चाहता है बल्कि अपने रिश्ते को रणनीतिक भागीदारी में पहुंचाना चाहता है। उन्होंने कहा, भारत केवल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार ही नहीं है बल्कि एक अहम रणनीतिक भागीदार भी है। डा. सुल्तान अहमद अल-जबर यहां पेट्रोटेक 2019 सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। डा. सुल्तान अहम से जब यह पूछा गया कि रत्नागिरी में प्रस्तावित छह करोड़ टन की रिफाइनरी में उनकी कंपनी एडीएनओसी कितनी हिस्सेदारी खरीदेगी तो जवाब में उन्होंने कहा, हम अभी शुरुआती दौर में हैं।

अनिल अंबानी समूह के गिरवी रखे शेयरों की बिक्री का मामला सेबी पहुंचा, होगी जांच

नई दिल्ली, 12 फरवरी (ए)। अनिल धीरुभाई अंबानी समूह (ष्ठत्र) की कंपनियों के गिरवी रखे गए शेयरों की बिक्री का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक शेयरों की बिक्री का मामला अब बाजार नियामक सेबी तक पहुंच गया है।

दरअसल दो कर्जदारों ने एडीएजी समूह की तीन लिस्टेड कंपनियों के गिरवी रखे शेयरों की बिक्री की थी, जिसके बाद इनके शेयर धाराशायी हो गए थे। रिलायंस समूह ने लार्सन एंड टुब्रो फाइनैंस और एडेलविज ग्रुप की कंपनियों पर अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के गिरवी रखे गए शेयरों को अवैध और गलत मंशा से बेचने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से इन कंपनियों के शेयरों के भाव में जबरदस्त गिरावट आई है।

शुक्रवार को रिलायंस ग्रुप ने आरोप लगाया कि एलएंडटी फाइनैंस समेत एडलविज ग्रुप की कुछ इकाइयों ने चार से सात फरवरी के बीच खुले बाजार में उसकी इकाइयों के करीब 400 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेच लिए। रिलायंस ग्रुप ने कहा कि इन दोनों कंपनियों के इस गैरकानूनी, भड़काऊ समझ से परे कदम से उसके बाजार पूंजीकरण में सिर्फ चार दिनों में 13,000 करोड़ रुपये की गिरावट आई है।

हालांकि एलएंडटी फाइनैंस और एडेलविज ग्रुप ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए रिलायंस समूह पर समय पर भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समय पर भुगतान नहीं किए जाने की वजह से ही उन्होंने खुले बाजार में गिरवी रखे गए शेयरों की बिक्री कर दी। अधिकारियों ने कहा कि

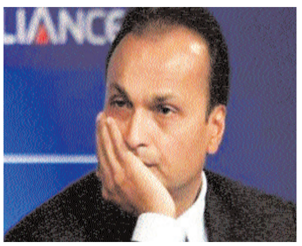

सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों से इन शेयरों की बिक्री के मामले को देखने को कहा है। साथ ही उसने इससे जुड़ी सभी अहम जानकारियां मांगी है, ताकि यह देखा जा सके कि कहीं किन्हीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। रिलायंस पावर ने सेबी को पहले ही इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। साथ ही उन कंपनियों पर रोक लगाने के लिए कहा है, जिन्होंने बाजार भाव से बेहद नीचे कीमत पर शेयरों की बिक्री कर दी। कंपनी ने सेबी से इस मामले की विस्तार से जांच करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने भी सेबी से ऐसी ही शिकायत की है। जब इस मामले में रिलायंस ग्रुप के प्रवक्ता से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, 'समूह की संभी कंपनियों के लिए गए संकल्प के मुताबिक हम अपने हितधारकों के हितों की सुरक्षा और उसके मूल्यों को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कानूनी कदम उठाएंगे।' वहीं एलएंडटी फाइनैंस और एडेलविज ने इस मामले में पूर्व में जारी किए गए बयानों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में रिलायंस पावर ने कहा है कि गिरवी रखे गए शेयरों की बिक्री से कंपनी के बाजार पूंजीकरण में तेज गिरावट आई। वहीं रिलायंस कैपिटल ने कहा कि इससे 8 लाख शेयरधारकों के हितों पर असर हुआ है। जबकि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने एलएंडटी फाइनैंस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके शेयरों की बिक्री से कंपनी के बाजार पूंजीकरण में गिरावट आई और करीब 8 लाख शेयरधारकों का हित प्रभावित हुआ।